यूनान चुनाव, 2015: सिरीजा की जीत का अवलोकन

डॉ. दिनोज कु. उपाध्याय*

आम चुनाव में सिरीजा पार्टी की जीत के साथ ही यूनान में स्पष्ट मितव्ययिता विरोधी मंच पर एक नई सरकार का गठन हुआ है। नए/नवनिर्वाचित प्रधान मंत्री एलेक्सीस सिप्रास ने यूनान पर थोपे गए मितव्ययिता के उपायों का खुलेआम विरोध किया था और विशाल अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अनुदानों/बेलआउट पर नए सिरे से वार्ता करने का वचन दिया। कांटे की टक्कर वाले इस चुनाव में सिरीजा पार्टी 300 सीटों वाली संसद में लगभग 36 प्रतिशत मत और 149 सीटों के साथ सत्ता में आई जो पूर्ण बहुमत से केवल दो कम थी। आम चुनावों में जीत के बाद एलेक्सीस सिप्रास ने 'यूनान के पांच वर्षों के तिरस्कार और दंश' का अंत करने का वायदा किया और कहा, "यूनान अब (नई) आशा के साथ आगे बढ़ेगा तथा यूरोप तक (अपनी) पैठ बनाएगा और यूरोप तो बदलेगा ही। यह (जीत) स्पष्ट जीत है। हम मितव्ययिता के क्रूर चक्र को समाप्त कर देंगे।" जैसा कि अनुमान था, वामपक्षी, मितव्ययिता विरोधी सिरीजा की जीत का पूरे यूरोपीय संघ पर 'दूरगामी प्रभाव' होगा और यह 'पूरे यूरोप के व्यापक आर्थिक एजेंडे में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकेगा, जैसाकि ऐलेनी पैनाजियोटारिया, अनुसंधान अध्येता, एलियामेप ने उल्लेख किया। यूरोपीय संसदीय चुनाव, 2014 में *यूरोसेप्टिक* और घोर दक्षिणपंथी दलों के उत्थान के आलोक में सिरीजा के पक्ष में राजनीतिक जनादेश और मितव्ययिता विरोधी दृष्टिकोण को लोकप्रिय समर्थन से यूरोजोन की राजनीति की गतिशीलता प्रभावित हो सकती है।

वर्तमान में, यूनान बड़ी आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसकी अर्थव्यवस्था यूरो जोन संकट के प्रारंभ के बाद से 25 प्रतिशत तक सिकुड़ चुकी है और बेरोजगारी बढ़कर 25 प्रतिशत हो गई है। यह गंभीर चिन्ता का विषय है कि युवाओं में से आधे बेरोजगार हैं। इस देश का ऋण बढ़कर इसके सकल घरेलू उत्पाद का 175 प्रतिशत हो गया। हजारों व्यापार बन्द हो चुके थे। मितव्ययिता के उपायों के गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी परिणाम हुए। यूनान के नए वित्त मंत्री

यानिस वारूफाकिस ने बताया कि मितव्ययिता व्यवस्था "राजकोषीय नौकायन नीतियों की तरह थीं जिसने यूनान को कर्जदार कॉलोनी में बदल दिया।" प्रधान मंत्री एलेक्सीस सिप्रास ने न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोत्तरी करके, करों में कटौती करके और सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देकर देश के इस 'मूक तिरस्कारपूर्ण संकट' का सामना करने की कसम खाई है। यूनान की जनता ने तो अपना जनादेश दे दिया है; अब नई सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने वायदों पर काम करके दिखलाए और लोगों को आर्थिक तंगी से राहत दिलाए। हालांकि एलेक्सीस सिप्रास ने प्रमुख निजीकरण परियोजनाओं को बंद करना और अनेक अप्रिय उपायों/निर्णयों को पलटना प्रारंभ कर दिया है, फिर भी, व्याप्त/मौजूदा आर्थिक परिस्थिति में उनके लिए वायदों को पूरा करना अत्यंत कठिन होगा।

यूरोपीय संघ यूनान की नई सरकार की नीतियों के प्रति सतर्क प्रतीत होता है। इस सरकार को यूरोपीय संघ में मितव्ययिता के रूख को छोड़ देने के लिए समर्थन नहीं मिल रहा है। यूरोपीय संघ के नेताओं ने मांग की है कि यूनान को मितव्ययिता और सुधारात्मक नीतियों पर कायम रहना चाहिए। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जीन क्लाउड जंकर ने यूनान के विशाल ऋण को रद्द करने के विकल्प से इनकार कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया कि "हम यूनान में लोकप्रिय मत का सम्मान करते हैं, लेकिन यूनान को भी दूसरों का सम्मान करना होगा।" उन्होंने यह भी कहा, "सिप्रास वायदा करते हैं कि यूनान मितव्ययिता को अब और स्वीकार नहीं करेगा। यूरो देशों का उत्तर है कि यदि यूनान अपने वायदों को छोड़ता है तो अब उसे और ऋण नहीं मिलेगा।" यूरोपीय केन्द्रीय बैंक (इसीबी) ने भी यूनान के बैंकों के वित्तपोषण को प्रतिबंधित करके अपना रूख कड़ा कर लिया है। यूरोपीय केन्द्रीय बैंक (इसीबी) अब व्यावसायिक बैंकों को धनराशि उधार देने के बदले यूनानी सरकार के बांडों को जमानत के रूप में स्वीकार नहीं करेगा; परिणामस्वरूप, यूनान के बैंकों के लिए नकद प्राप्त करना ज्यादा महंगा हो जाएगा। यूरोपीय केन्द्रीय बैंक (इसीबी) ने सौदा हो जाने का संकेत दिया है, दोनों ही परिस्थितियों में इसके निहितार्थ होंगे।

यानिस वारूफाकिस ने व्यापक आर्थिक अनुदानों/बेलआउट पर फिर से बातचीत करने के अपने सरकार के कदम के पक्ष में समर्थन जुटाने हेतु अनेक यूरोपीय राजधानियों का दौरा किया है। जर्मनी ने यूनान के ऋण को रद्द करने से इनकार कर दिया। अन्य देश जैसेकि फिनलैण्ड ने संकेत दिया कि यूनान की ऋण अदायगी अवधि बढ़ाई जा सकती है लेकिन ऋण को रद्द करना संभव नहीं होगा। इटली के प्रधान मंत्री मत्तेयो रेन्जी ने यूनान के लिए उत्साहवर्धक वक्तव्य दिया और आर्थिक अनुदानों/बेलआउट पर फिर से बातचीत करने के यूनान के रूख का भी समर्थन किया। विश्लेषक मानते हैं कि यूनान में सिरीजा की जीत अन्य जनवादी दलों को प्रोत्साहित कर सकती है, जैसेकि इटली में *बेपे ग्रिलो* का यूरो-

विरोधी पांच सितारा आन्दोलन और स्पेन में *पोडेमस* आन्दोलन। ऋणदाताओं में डर है कि मितव्ययिता उपायों को अपना रहे देशों में ऐसी मांग बढ़ सकती है। थामस राइट, निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था तथा कूटनीति परियोजना, ब्रुकिंग्स, ने तर्क दिया है कि प्रमुख पार्टियों को यूरोजोन पर थोपे गए जर्मन आर्थिक कट्टरता के कारण बदनाम किया जा रहा है और इसके कारण जनवादी कट्टरपंथी पार्टियों का उत्थान हुआ है।

सिरीजा की जीत रूस के प्रति यूरोपीय संघ की नीति, विशेषकर यूक्रेन संकट के कारण रूस पर आर्थिक प्रतिबंध (की नीति) पर टकराव पैदा कर सकती है। यूनान ने रूस के विरूद्ध और अधिक प्रतिबंधों के आह्वान का विरोध किया है। श्री सिप्रास पहले ही रूस के विरूद्ध यूरोपीय संघ के प्रतिबंध को 'अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने' के समान बता चुके हैं। यूनान में रूस के राजदूत आन्द्रे एम. मासलोव एलेक्सीस सिप्रास के कामकाज संभालने के बाद उनसे मिलने वाले प्रथम विदेशी गणमान्य व्यक्ति थे। चुनावों से पहले श्री सिप्रास ने मई, 2014 में रूस का दौरा किया था। वे पूरब की ओर नाटो के अब और अधिक विस्तार का समर्थन नहीं करते और यूरोपीय संघ द्वारा रूस के प्रति रचनात्मक नीति की वकालत करते हैं।

अंत में, यूरोपीय नीतियां कैसा स्वरूप प्राप्त करेंगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि ब्रुसेल्स और एथेन्स भविष्य में कार्रवाई की दिशा कैसे तय करते हैं। जैसाकि हाल का रूझान प्रदर्शित करता है कि यूनान यूरोजोन में बने रहना तो चाहता है लेकिन यह मितव्ययिता के उपायों से सहमत नहीं होगा। यूरोपीय नेता भी किसी समझौते पर जोर दे रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि यूनान एकल मुद्रा जोन में बना रहेगा। जर्मन चान्सलर ऐंजेला मार्केल ने विचार व्यक्त किया, "मैं चाहती हूं कि कठिनाइयों के बावजूद यूनान हमारी कहानी का हिस्सा बना रहे।" आने वाले समय में यह देखा जाएगा कि क्या यूरोपीय संघ और यूनान अपनी संकट का कार्यात्मक समाधान तलाशने में सफल हों पाएंगे अथवा वे (ऐसे) टकराव का रास्ता चुनेंगे, जो यूरोपीय संघ में आर्थिक स्थिरता के लिए गंभीर संकट पैदा कर सकता है।

****

*डॉ. दिनोज कु. उपाध्याय विश्व मामलों की भारतीय परिषद, सप्रु हाउस, नई दिल्ली में अनुसंधान अध्येता हैं।